

THE MINISTER OF COMMERCE  
(SHRI RAMAKRISHNA HEGDE): (a)  
Yes, Sir.

(b) and (c) Apart from the general trade policy reforms, some of the steps taken to enhance exports of spices include abolition of cess on export of pepper (except green pepper in brine), cardamom, saffron and spice oils and oleoresins to make them price competitive in the overseas markets; implementation of brand promotion schemes like "Logo Promotion"; grant of "Spice House Certificate" as a recognition of processor/exporter of quality products; setting up of laboratories for testing of products to ensure quality; technology transfer; process upgradation and product development.

(d) Review of taxation burden on exports, including cess, is an ongoing process and as and when considered necessary, exemptions on specified items of spices are notified with a view to make our exports more competitive in the international market. Cess on export of pepper (except green pepper in brine), cardamom, saffron and spice oils and oleoresins has been exempted.

**खुला सामान्य लाइसेंस (ओ जी एल) योजना के अन्तर्गत तिलहन का आयात**

2170. श्री बरजिन्दर सिंह :  
श्री सुखदेव सिंह ठिंडसा :

क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि देश में तिलहन की कमी को दूर करने के लिए अनेक संस्थान में केन्द्र सरकार से तिलहन-बीजों को खुला सामान्य लाइसेंस (ओ. जी. एल) योजना के अन्तर्गत आयात करने की छूट देने की मांग की है,

(ख) यदि हां, तो यह मांग किन-किन संस्थानों द्वारा कब की गई थी,

(ग) क्या सरकार ने इस मांग पर विचार करने के पश्चात् इसे स्वीकार करने का कोई निर्णय भी लिया है, और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी विस्तृत ब्यौरा क्या है ?

**वाणिज्य मंत्री (श्री रामकृष्ण हेगड़े) :** (क) और (ख) सोयाबीन प्रोसेसर एसोसिएशन आफ इंडिया (सोपा), दि सॉल्वेंट एक्सट्रेक्टर्स एसोसिएशन आफ इंडिया (एसईए) और भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग मंडल परिसंघ (फिक्की) ने सोयाबीन बीजों एवं अन्य तेल-बीजों के आयात की अनुमति देने का प्रस्ताव किया था।

(ग) और (घ) कुछेक शर्तों और प्रक्रियागत अपेक्षाओं के अधीन रहते हुए घरेलू उपलब्धता में वृद्धि करने के निमित्त सीमित मात्रा में सोयाबीन के आयात की अनुमति देने से संबंधित एक प्रस्ताव पर इस समय विचार किया जा रहा है।

**रबड़ की मांग और पूर्ति**

2171. डा. रणवीर सिंह :  
श्री रामनाथ कोविन्द :  
श्री राजनाथ सिंह "सूर्य" :

क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि प्राकृतिक और सिन्थेटिक रबड़ दोनों की मांग और पूर्ति के बीच हर वर्ष अन्तर बढ़ता जा रहा है,

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं, और

(ग) सरकार ने इस अंतर को दूर करने के लिए क्या कदम उठाये हैं ?

**वाणिज्य मंत्री (श्री रामकृष्ण हेगड़े) :** (क) प्राकृतिक रबड़ के उत्पादन और खपत के बीच अंतर